>

Title : Need to prevent the entry of multinational companies in retail sector in the country.

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): केन्द्र सरकार देश के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देने जा रही है। इसके लिए एक परिचर्चा पत्र जारी कर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने राय मांगी है। यदि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुदरा व्यापार में उतरीं तो देश के करीब पांच करोड़ छोटे व्यापारी और लगभग इतने ही ऐसे लोग, जो रिटेल व्यापार से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी के कगार पर पहुंच जायेंगे। इतना ही नहीं इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा सीधे खेतों से उत्पाद खरीदकर बेचे जाने की नीति से हमारी कृषि मंडियों का ढांचा ही खत्म हो जायेगा। साथ ही आढ़तियों का कारोबार सिमट जायेगा। ऐसे में महोदय कुछ समय बाद ये कम्पनियां कृषि उत्पादों की सबसे बड़ी खरीददार हो जायेंगी और कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण इनके हाथों में चला जायेगा और हमारे किसान इनके हाथों की कठपुतली बन जायेंगे। खुदरा व्यापार में ऐसे विदेशी निवेश का पहले से ही विरोध हो रहा है। जून, 2009 में वाणिज्य मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी इसके विरोध में कड़ी टिप्पणी की गई है। आपसे अपेक्षा है कि एक ओर जहां सरकार द्वारा देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है वहीं दूसरी ओर खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न्यौता देकर करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने एवं किसानों को बंधुआ बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है।